लोकतंत्र

"मजदूरों की
नहीं तो यह समस्त
लोकतांत्रिक शक्तियों
की लड़ाई है"
— दत्तोपंत ठेंगड़ी

प्रकाशक :
लोकहित प्रकाशन
राजेन्द्र नगर (पूर्व)
लखनऊ

निवेदन

प्रख्यात चिन्तक और भारती मजदूर संघ के संस्थापक श्री दत्तोप ठेंगड़ी ने अपनी आयु के ६० वर्ष किये ।

इस अवसर पर देश भर में उनके सत्कार के कार्यक्रम सम्पन्न हुए जिनमें उन्होंने आज देश में लोकतंत्र को पुनः समाप्त करने के षड़यंत्र की विस्तार से चर्चा की और साम्राज्यवादी दुष्चक्र से देश के सार्वभौमत्व व स्वतंत्रता की रक्षा हेतु राष्ट्रभक्त नागरिकों से अपील की ।

आशा है कि सामयिक मार्गदर्शन की दृष्टि से यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

मकर संक्रांति
सन् १९८२

—प्रकाशक

मूल्य : रु० १.००

मुद्रक ।
कौशल प्रेस
लखनऊ

प्रेम यह मैग्नीफाइंग ग्लास

आज के इस अवसर पर क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए यह मैं तय नहीं कर पा रहा हूं। हमेशा सभायें होती हैं, हम भाषण भी देते हैं किन्तु आज का अवसर कुछ दूसरे ढंग का है जिसमें आप लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं। ऐसे सत्कार सभा में क्या बोलना चाहिए इसका मुझे पता नहीं। क्योंकि जिस अखाड़े से मैं आया हूं उस अखाड़े में कोई किसी का सत्कार करता ही नहीं, सभी लोग कार्य करते जा रहे हैं—२० साल, ४० साल, ५० साल—लेकिन कोई किसी का सत्कार नहीं करता। इसके कारण ऐसे अवसर पर किस ढंग से बोलना चाहिये—इस असमंजस में मैं हूं। दूसरी बात—मेरे विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे गए हैं। यह तो हमारे साथियों का प्रेम है। प्रेम यह मेगनीफाइंग ग्लास के समान होता है मेगनीफाइंग ग्लास में छोटी चीज बहुत बड़ी दिखाई देती है। वैसे ही प्रेम के कारण मेरे सहकारियों को मेरा छोटा काम भी बहुत बड़ा मालूम होता है। भारतीय मजदूर संघ आज एक विशाल स्वरूप धारण कर चुका है यह बात ठीक है, लेकिन यह मेरे कारण है यह कहना केवल अतिश्योक्ति ही नहीं तो यह गलत होगा। मैं कई नेताओं से, सार्वजनिक जीवन में यह शिकायत सुनते रहता हूं कि जनता कृतघ्न है—हम देश के लिए कितने बर्बाद हुए हैं लेकिन जनता ने उसका कुछ भी महत्व नही माना—ऐसी शिकायत मैं सुनते रहता हूं। लेकिन मेरे विषय में कुछ उल्टा मामला ही मालूम होता है। मेरे जन्म-पत्री में शनि व मंगल ऐसे स्थान पर बैठा है, कि काम तो मेरे सहकारी करते रहते हैं और काम में यदि यश प्राप्त हुआ,

तो उसका श्रेय वे मेरे ओर खिसका देते हैं। काम में यदि असफलता हुई तो उसका अपयश वे स्वयं लेते हैं। इसके कारण जो मेरा बैंक एकाउन्ट देखता है उसको केवल श्रेय ही श्रेय दिखाई देता है, लेकिन यह हमारे द्वारा जमा किया हुआ श्रेय नहीं है। हमारे साथियों द्वारा जमा किया हुआ यश है। लेकिन इसके कारण एक आभास होता है कि मैंने कुछ वहुत बड़ा काम किया है।

यह व्यक्ति का नहीं—सिद्धान्त का सम्मान है

वैसे अपने देश में यह एक पद्धति है कि प्रेम के कारण किसी को भी अति श्रेष्ठ बताना, जो वास्तव में वास्तविकता से दूर है। एक छोटा-सा प्रसंग याद आता है—पूज्य महात्मा जी गुरुदेव के निमंत्रण पर शांति निकेतन कुछ दिन के लिए गए थे। तो एक विदेशी पत्रकार ने कुछ प्रश्न दोनों को अलग-अलग पूछे। उसमें से एक प्रश्न यह था कि आज का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? पहले महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने जवाब दिया--'मैं और किसी को नहीं जानता—गुरुदेव के अतिरिक्त। यानी सबसे श्रेष्ठ कवि गुरुदेव हैं। वही प्रश्न गुरुदेव से पूछा। उन्होंने जो उत्तर दिया वह ध्यान के रखने लायक है। उन्होंने कहा कि निसर्ग को सर्वश्रेष्ठ मान्य नहीं है—कोई श्रेष्ठ हो सकता है किन्तु सर्वश्रेष्ठ नहीं। तो प्रेम के कारण, एक पद्धति के कारण अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन उसमें सचाई कितनी है—यह भी ध्यान में रखना चाहिये।

हम ही किसी पत्थर को सिन्दूर लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि यह हनुमान जी हैं और उसके सामने हम ही प्रणाम करते हैं। ऐसा ही कार्यकर्ताओं का कुछ इस अवसर पर हो रहा है। ऐसा मुझे लगता है। यह जो सारा उपक्रम हुआ है इसमें कई लोगों ने सहयोग दिया। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने तो काम किया ही है, उसके अलावा भी जिनका मजदूर क्षेत्र से सीधा सम्बन्ध नहीं लेकिन जिनके मन में यह विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ केवल ट्रेड यूनियन नहीं है तो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख माध्यमों में से एक माध्यम यह भारतीय मजदूर संघ है ऐसा विश्वास जिनके मन में है ऐसे देशभक्त नागरिक बन्धुओं ने भी इसमें सहयोग दिया

है। मैं हृदयपूर्वक आप सब बन्धुओं का धन्यवाद करता हूं—आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। यह व्यक्ति का सम्मान नहीं है तो एक संगठन और एक सिद्धांत—एक आदर्श— इसके प्रतिनिधि के रूप में ही यह सम्मान हो रहा है अतः सभी बन्धुओं का जिन्होंने इस कार्य में 'पत्रम पुष्पम फलम् तोयम्' सहयोग दिया है—सभी के प्रति अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

श्रमिक जगत पर कुठाराघात

वैसे देखा जाए तो सत्कार समारोह यह आनन्द का ही विषय होना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियाँ आज देश में और मजदूर क्षेत्र में हैं, उनको देखते हुए किसी को भी आनन्द होना, बड़ा कठिन काम है। देश की भी स्थिति, मजदूरों की भी स्थिति आज बहुत ही शोचनीय है। जहाँ तक मजदूर क्षेत्र का सम्बन्ध है हम सब लोग जानते हैं कि इस समय सरकार ने एक बहुत बड़ा हमला मजदूर आंदोलन पर किया हुआ है। अभी-अभी जो आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून पास हुआ, वह मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को छीनने वाला है और इस तरह एक कुठाराघात मजदूर आंदोलन पर सरकार ने किया है। इतना बड़ा आघात करने की आवश्यकता क्या थी, इसका विचार आप सबने किया ? तो आपको आश्चर्य होगा कि पिछले दो साल में कोई भी ऐसी अभूतपूर्व अनोखी घटना नहीं हुई थी कि जिसके कारण यह अभूतपूर्व अनोखा कदम उठाने की आवश्यकता किसी भी समझदार सरकार को प्रतीत हो।

'पिछले दो साल में उत्पादन की मात्रा वही रही जो हमेशा रहती थी। नष्ट हुए श्रम-दिनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं थी, हड़तालों की संख्या उतनी ही थी जितनी हमेशा रहती है, कोई भी अनोखी बात नहीं हुई थी कि जिसके कारण यह हमला करना उचित था तो भी यह हमला हुआ है। इस तरह का हमला करने की हिम्मत सरकार को क्यों हुई—इसका गम्भीरता से सभी लोगों ने विचार करना आवश्यक है।

सरकारी कुप्रचार

पहली बात यह ख्याल में आती है कि पिछले ३४ साल में सरकार

ने मजदूरों के विषय में तरह-तरह की गलतफहमियाँ फैलाने का कार्य जारी रखा है। डा० गौबेल्स का सिद्धांत था कि कोई भी झूठ बात आप एक सौ बार दोहराइये—तो बार-बार कहने के कारण सुनने वाले को यह लगेगा कि यह सच्चाई है। भारत सरकार ने इसी का प्रयोग किया है। और इसके कारण मजदूरों के बारे में प्रेम रखने वाले लोग भी मजदूर आंदोलनों के विषय में काफी गलतफहमी रखते हैं। गलत प्रचार तो तरह-तरह का है किन्तु केवल १-२ उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे आमतौर पर, कहा जाता है कि भाई मजदूर गैर-जिम्मेवार है। वास्तव में उसी समय सरकार यह भी कहती है कि इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि हुई। अरे! मजदूर अगर गैर जिम्मेवार है तो उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी ? दो परस्पर विरोधी वक्तव्य सरकार के लोग एक ही समय में करते रहते हैं। फिर भी लोगों में एक बात फैल गई है कि मजदूर गैर जिम्मेवार है।

वायुमण्डल का सम्पूर्ण समाज पर स्वाभाविक परिणाम

कभी-कभी बात करने का मौका आता है, किसी ने कहा कि तुम्हारे मजदूर बड़े गैरजिम्मेवार हैं। हमने प्रति प्रश्न किया कि हमारे देश में ऐसे और कितने हैं जो लोग गैर जिम्मेदार नहीं हैं इसकी सूची दीजिये। वास्तव में मजदूर क्षेत्र—यह समाज से कटा हुआ क्षेत्र नहीं है। सम्पूर्ण समाज में जो वायुमण्डल होगा उसका स्वाभाविक परिणाम मजदूर क्षेत्र पर भी होता है, जैसे विद्यार्थी क्षेत्र पर भी होता है, हर क्षेत्र पर होता है। सम्पूर्ण समाज में वायुमण्डल, यदि स्वार्थ का, गैर जिम्मेवारी का, राष्ट्रभक्ति-विहीनता का होगा तो केवल एक किसी क्षेत्र में—यह चाहे मजदूर क्षेत्र ही क्यों न हो, दूसरा वायुमण्डल मिलना चाहिए ऐसी अपेक्षा रखना एक अवास्तविक बात है आज समाज का वायुमण्डल क्या है यह देखना चाहिये। किसी भी समाज में, जो मनोवैज्ञानिक वायुमण्डल बनता है, उसमें पहल करने का काम हमेशा नेताओं का हुआ करता है क्योंकि नेताओं का जैसा व्यवहार रहेगा उसी का अनुकरण बाकी लोग करते हैं।

आज जिनको देश के शीर्षस्थ नेता माना गया है, वे लोग इस देश के सर्वोच्च मंच पर—पार्लियामेंट में—एक दूसरे को गाली-गलौज कर रहे हैं,

एक दूसरे पर उछल रहे—जो ज्यादा प्रगतिशील व क्रान्तिकारी हैं वे एक दूसरे पर जूते भी निकाल रहे हैं—यह समाचार अगर हमारे मजदूर व विद्यार्थी हर दिन समाचार पत्र में पढ़ते हैं—और फिर उनसे यह अपेक्षा की जाये कि नेता तो अनुशासन विहीन रहें और बाकी लोगों को अनुशासन का पालन करना चाहिये—तो यह गलत बात होगी ।

गैर जिम्मेवार वायुमण्डल के लिये नेता दोषी हैं

यह ठीक है कि हम राष्ट्रभक्त हैं हम उत्पादन में बाधा लाना नहीं चाहते, अनुशासन से रहना चाहिए ऐसी हमारी इच्छा है। जिम्मेवारी की भावना का प्रचार हम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं—लेकिन उसको सीमित यश को प्राप्त होता है क्योंकि समाज में फैला हुआ अनुशासनहीनता का व गैर जिम्मेवारी का वायुमण्डल है, जिसके लिए वास्तव में जिम्मेवार नेता हैं। इसके लिये यदि कोई उपाय-योजना होगी वह यही हो सकती है कि आज जिनको समाज के नेता—माना जाता है उनका व्यवहार आदर्श रहना चाहिये या जिनका व्यवहार आदर्श है ऐसे लोगों को नेता मानने की आदत समाज को लगनी चाहिए। दोनों में से एक बात जब तक नहीं होती तब तक यह वायुमण्डल दुरस्त नहीं हो सकता। इतना खराब वायुमण्डल होते हुए भी हिन्दुस्थान का मजदूर उत्पादन बढ़ा रहा है, काम बराबर कर रहा है, और इतना ही नहीं तो जब कभी देश पर संकट आता है—१९६२ में चीन के आक्रमण के समय, ६५ में पाकिस्तान के आक्रमण के समय, ७१ में बंगलादेश की लड़ाई के समय, मजदूरों ने ज्यादा घण्टों काम किया है। अतिरिक्त भत्ता न लेते हुए, स्वयं गरीब रहते हुए सुरक्षा कोष में पैसा दिया। स्वयं दुबले-पतले रहते हुए ब्लडबैंक में अपना खून जमा किया है, जवान के नाते लड़ने के लिए अपने नाम दिये हैं, और इतना ही नहीं तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि १९६५ की लड़ाई के समय, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, पाकिस्तान की सीमा पर अपनी युद्ध-सामग्री बचाने के लिए, हमारे कुछ रेल कर्मचारी बन्धुओं ने अपनी जान भी कुर्बान की है। यह सारा होते हुए भी आज आम आदमी के दिमाग में यह बात बैठी है कि सबसे ज्यादा गैर जिम्मेवार मजदूर हैं तो इसका कारण एक ही है कि

सरकार की ओर से लगातार यह प्रचार हो रहा है। इस तरह के गलत प्रचार के प्रतिवाद करने का काम, आम जनता को विश्वास में लेकर मजदूरों की बात उनको समझाने का काम भारतीय मजदूर संघ के पूर्व काम करने वाले किसी भी यूनियन ने नहीं किया, इसी के कारण यह सारा गलत प्रचार बड़ा प्रभावी हुआ है।

उत्पादन की कमी के अनेक कारण

दूसरा उदाहरण आपके सामने देता हूं। सरकार ने निरंतर यह प्रचार किया कि उत्पादन में जो कुछ भी कमी होती है उसका प्रमुख कारण मजदूरों की हड़तालें हैं और दूसरा प्रचार किया कि मजदूरों का पैसा बढ़ने के कारण, मँहगाई बढ़ती है। भारतीय मजदूर संघ ने इन दोनों बातों के विषय में प्रारम्भ से जनता को सुशिक्षित करने का प्रयास किया था कि यह दोनों आरोप गलत हैं। आज सौभाग्य से एक निष्पक्ष संस्था जिसका नाम है Indian Institute of Public Administration जिसने पिछले जुलाई-अगस्त महीने में, इन्हीं दोनों विषयों का अध्ययन व सर्वेक्षण किया और उन्होंने अपने निष्पक्ष निष्कर्ष प्रकाशित किये हैं। हमारे लिए यह आनन्द का विषय है कि भारतीय मजदूर संघ ने प्रारम्भ से जो प्रतिपादन किया था वह और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के निष्कर्ष दोनों ही एक जैसे हैं। इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट कहा है कि उत्पादन में जो घट होती है उसके लिए मजदूरों की हड़तालें तो एक नगण्य कारण है, वास्तव में उत्पादन में घट आने के और भी बड़े कारण हैं। वे कारण उन्होंने बताये कि अव्यवस्था, कच्चा माल समय पर न मिलना, मशीनरी का खराब हो जाना, बिजली की कमी व उसकी रुकावट, बाजार की गलत पालिसी रहना, निर्यात की सुविधायें उपलब्ध न होना—यह बड़े कारण हैं।

मँहगाई बढ़ने के तीन कारण

मँहगाई बढ़ने के तीन प्रमुख कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से कहे एक घाटे की अर्थव्यवस्था, दूसरा काला पैसा और तीसरा अनियंत्रित लाभांश

और ब्याज। हम सब लोग जानते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में है और डिफीसिट फाइनेनसिंग की मात्रा निरंतर बढ़ाने का काम स्वयं सरकार करती है। जो काला पैसा कमाते हैं उनको नजदीक के खम्बे पर फाँसी दी जायगी ऐसा स्व० जवाहरलाल जी ने कहा था लेकिन अभी पिछले साल काला पैसा कमाने वाले को सरकार ने अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र दिया है। धारक बांड स्कीम निकाल कर उनको कहा है कि और काला पैसा कमाओ हमें कोई आपत्ति नहीं आप काला पैसा कमाते जाइये उसको सफेद करने का काम भारत सरकार करती रहेगी; इस तरह का उनको आश्वासन दिया है, उनकी पीठ थपथपाई है। लाभांश व ब्याज का नियंत्रण करने की हिम्मत भारत सरकार की नहीं है, यह बात तो साफ है। याने जो प्रमुख कारण मँहगाई बढ़ने के हैं, उसके लिए जिम्मेवार स्वयं सरकार है लेकिन बलि का बकरा मजदूरों को बनाया जाता है। हालांकि इंस्टीट्यूट के निष्कर्ष के अनुसार मजदूरों का बढ़ा हुआ पैसा जिसका बहुत थोड़ा असर नगण्य प्रभाव मँहगाई पर होता है।

एक गलतफहमी

सरकार के गलत प्रचार के कारण, अखंड प्रचार के कारण सुशिक्षित लोगों के मन में भी, ये दोनों गलतफहमियाँ जमकर बैठ गयी हैं। इसका परिणाम क्या होगा? ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जिस तरह समाज से सम्पर्क रखना चाहिए था उस तरह नहीं रखे, इसके कारण, जब कभी सरकार के साथ संघर्ष होता है, मजदूरों की बात आम जनता के ख्याल में नहीं आती। वास्तव में दृश्य तो ऐसा उपस्थित होना चाहिए, कि मजदूर और आम जनता एक तरफ, अकेली सरकार एक तरफ। किन्तु ऐसा दृश्य निर्माण होता है कि मजदूर अकेला एक तरफ, और आम जनता सरकार के साथ खड़ी है। मजदूर अकेला पड़ता है सरकार अकेली नहीं पड़ती। आम जनता को विश्वास में, लेकर खुद से अपनी बात समझाने का काम भारतीय मजदूर संघ के पूर्व यूनियनों ने नहीं किया इसके कारण सरकार का हौसला बढ़ गया है। दूसरी बात, जिस देश में मजदूर एकता कायम हुई है, वहाँ मजदूरों की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि सरकार को भी उनके कहने के

अनुसार विचार करना पड़ता है। उनका प्रभाव रहता है। पोलिटिकल यूनियनइज्म के कारण, एक-एक कारखाने में, एक-एक उद्योग में चार-चार पांच-पांच मजदूर संघ खड़ी हो जाती हैं। आज भी हमारे देश में, हर जगह चार, पांच, छै यूनियनें खड़ी हम देखते हैं इसका कारण यही है, पोलिटिकल यूनियनइज्म यदि राजनैतिक मजदूर संघों के सिद्धांत को स्वीकार किया, तो हर एक कारखाने में, उतनी यूनियनें बनने की गुंजाइश हो जायेगी जितनी राजनैतिक पार्टियाँ हिन्दुस्थान में हैं। इससे मजदूर बँट जाता है उसकी सामूहिक सौदे की ताकत और संघर्ष करने की शक्ति घट जाती है। इसका लाभ सरकार उठा सकती है।

गैर राजनीतिक आधार पर मजदूर संगठन आवश्यक

दुनिया का अनुभव यदि हम देखें, कई देशों में राजनैतिक मजदूर संघवाद चल रहा है। यह सिद्धांत कम्युनिस्टों का है, लेकिन बाकी लोगों ने भी उनका अंधानुकरण किया है। पश्चिम में जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी में पौलीटिकल यूनियनइज्म के कारण मजदूर बँट गया और इसके कारण वहाँ, मजदूरों की वास्तव में जितनी शक्ति है उसका सरकार पर प्रभाव नहीं है। इसके उलटे जिस देश को पूंजीवाद का अड्डा माना गया है, जहाँ कैपिटलिस्टों की ताकत बहुत ज्यादा है, वहाँ ऐसा नहीं है। अमेरिका में भारतीय मजदूर संघ के ही समान गैर राजनैतिक विशुद्ध मजदूर यूनियन के आधार पर मजदूरों के संगठन खड़े हैं। इसके कारण एक उद्योग में एक ही यूनियन है। यह बात ठीक है कि हरेक मजदूर जैसे मजदूर हैं, वैसे नागरिक भी हैं और नागरिक के नाते किसी भी पार्टी में काम करना या न करना उसका अधिकार है। लेकिन जहाँ तक यूनियन का सवाल है, उसे राजनीति में न लाया जाये। अलग-अलग राजनैतिक दलों में होते हुए भी, सभी मजदूर अपने हित के लिए एक यूनियन के मंच पर काम करते हैं। इस तरह की यूनियन अमेरिका में हैं और इसके कारण हरेक उद्योग में एक ही यूनियन है और अपनी एक-एक यूनियन को लेकर अमेरिकन फेडरेशन आफ लेबर बना है। अपनी एकता के कारण जो देश वास्तव में पूंजीवाद का गढ़ माना जाता है, उस अमेरिका में, मजदूरों की ताकत इतनी बढ़ी

हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी, जिसकी बहुत ज्यादा शक्तियाँ हुआ करती हैं, कोई भी नीति तय करते समय, केवल औद्योगिक और मजदूरों की नीति ही नहीं तो विदेश नीति तय करते समय भी, दस बार सोचना पड़ता है कि इस नीति के बारे में अमेरिका के मजदूरों की प्रति-क्रिया क्या होगी ? इसका प्रभाव विशुद्ध ट्रेड यूनियनइज्म के कारण पूँजीवाद के अड्डे में मजदूरों ने निर्माण की है।

जैसे पूँजीवादी देश का मैंने उदाहरण दिया, हम साम्यवादी देशों का भी विचार करें। राजनैतिक यूनियनइज्म कम्युनिस्टों का ही सिद्धांत है। लेकिन जहाँ-जहाँ कम्युनिस्टों का शासन आया, वहाँ-वहाँ मजदूरों ने इस सिद्धांत का विरोध किया है। रूस में भी हड़तालें होती रही हैं; पिछले साल भी हुई। हम जानते हैं किस तरह, १९५३ में पूर्वी जर्मनी में, १९५६ में हंगरी में, १९६८ में चेकोस्लोवाकिया में, वहाँ के मजदूरों ने राजनैतिक यूनियनइज्म का विरोध करते हुए कम्युनिस्ट सरकार के विरोध में बगावत की थी, यह इतिहास हमारे सामने है। अभी-अभी डेढ़ साल पहले, दूसरा एक कम्युनिस्ट शासित देश पोलैंड, वहाँ के मजदूरों ने कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ विद्रोह किया है। और विद्रोह करते समय उनकी सर्वप्रथम माँग यही थी कि हमें स्वतन्त्र गैर राजनैतिक मजदूर संघ बनाने का अधिकार होना चाहिये। वहाँ इस लड़ाई में सारे मजदूर एक हैं की वहां तानाशाही है तो भी इस संघर्ष में, मजदूरों की विजय हुई, सरकार की हार हुई और पोलैंड के अन्दर मजदूर इतना प्रभावी हो चुका है, कि आज आपने अखबार में यह पढ़ा होगा कि वे लोग अपनी मांगों को लेकर जब खड़े हुए तो सर-कार को वहां मार्शल-ला लाना पड़ा। याने बहुत बड़ी ताकत वहां खड़ी हुई है। इतनी सख्ती करने पर भी कम्युनिस्टों की नहीं चल रही है। वहां भी, स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के आधार पर मजदूरों ने इतनी बड़ी ताकत खड़ी की है इसलिए भारतीय मजदूर संघ का सिद्धांत, विशुद्ध, गैर राजनीतिक ट्रेड यूनियनइज्म किस तरह से मजदूरों को प्रबल बना सकता है यह बात हमारे ख्याल में आ सकती है। दुर्भाग्य से, हमारे यहाँ राजनैतिक यूनियनइज्म चल रहा है, मजदूर बँट गया है, संघर्ष की उसकी ताकत कम हो गयी है और इसके कारण उन पर हमला करने में सरकार को संकोच नहीं होता।

राष्ट्रहित की चौखट में मजदूर-हित—यह ध्येय

आज की जो परिस्थिति आयी इसमें यह तो आनन्द की बात है कि यह इतना भीषण संकट है यह समझ कर आज हिंदुस्थान की सभी ट्रेड यूनियनें केवल इंटक को छोड़कर, एक मंच पर आ गई हैं। नेशनल कम्पेन कमेटी के नाम से, उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। उस संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में देश में जगह-जगह तरह-तरह के कार्यक्रम हुए। पिछले २३ नवम्बर को दिल्ली में मजदूरों का एक विशाल प्रदर्शन पार्लियामेंट के सामने हुआ जिसमें १५ लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया था। और आने वाली १९ जनवरी को अपना निषेध प्रकट करने के लिए, हिंदुस्थान के सभी मजदूर एक दिन सांकेतिक हड़ताल पर जाने वाले हैं। यह एकता का दृश्य निर्माण हुआ, यह तो आनन्द की बात है। किन्तु इसी अवसर पर अन्य ट्रेड यूनियन के नेताओं व कार्यकर्ताओं को मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको यह सोचना चाहिये, कि वास्तव में यदि हम एकता चाहते हैं तो राजनैतिक यूनियनइज्म को छोड़कर जनरल ट्रेड यूनियन कहना उचित होगा या नहीं होगा, इस बारे में पुनः विचार करना चाहिये। और यदि पुनः विचार करते हुए सभी केन्द्रीय मजदूर संगठन यह निश्चय करती हैं, कि वे राजनैतिक यूनियनइज्म को छोड़ देंगे, किसी भी राजनैतिक दल के निमित्त काम नहीं करेंगे, केवल मजदूरों का ही हित, राष्ट्र हित के चौखट के अन्तर्गत मजदूरों का हित, यह एक ही ध्येय रखते हुए काम करेंगे, ऐसा यदि पांचों संगठन निश्चय करते हैं, तो मैं यहाँ घोषणा करना चाहता हूं कि उस अवस्था में, सबसे प्रथम भारतीय मजदूर संघ स्वयं अपने को समाप्त करने के लिए तत्पर है। क्योंकि हम संस्थागत हित को लेकर कार्य नहीं कर रहे। राष्ट्र और मजदूरों के हित के लिए हमारा काम है और इस दृष्टि से हम विसर्जित होने के लिए तत्पर रहेंगे यह आश्वासन मैं इस समय दे सकता हूं।

आर्थिक क्षेत्र की सभी घटनाओं के पीछे सूत्र एक

लेकिन यह देखना चाहिए कि इसी समय यह हमला क्यों ? जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले दो साल में कोई अभूतपूर्व घटना नहीं हुई जिसके

कारण इसकी आवश्यकता थी । फिर भी यह हमला क्यों हुआ ? यह देखने की आवश्यकता है । वैसे तो हमारे देश में दुर्भाग्य से जनता को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया ही बन्द है । जब कोई एकाध घटना हो जाती है तो उसके ऊपर नेताओं के वक्तव्य आ जाते हैं । मूल में क्या है, यह खोजने की कोशिश नहीं होती । आर्थिक क्षेत्र में तरह-तरह की घटनायें होती हैं । एक घटना हो गई एक वक्तव्य आ गया । उदाहरण के लिए हिंदुस्थान में पिछले साल ३६.६ लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ, तो भी अमेरिका से १५ लाख टन गेहूं क्यों मँगाया गया एक अलग घटना समझकर १०-५ नेताओं ने वक्तव्य दे दिये । सारी दुनिया में पेट्रो प्रोडक्टस की कीमत जब गिरती जा रही थी उसी समय हिंदुस्थान में पेट्रो प्रोडक्टस की कीमत बढ़ाई गई जिसमें मिट्टी का तेल, जो गरीब आदमी का है—वह भी शामिल है । एक केवल वक्तव्य आ गया, कि यह नहीं बढ़ाना चाहिए था, १०-५ नेताओं ने वक्तव्य दे दिये, वास्तव में जितनी घटनायें आर्थिक क्षेत्र की हैं, यह देखने में अलग-अलग दीखती होगी लेकिन इन सबके पीछे एक सूत्र है । जैसे किसी को बार-बार फोड़ा-फुन्सी होती है, एक जगह फोड़े की मलहम पट्टी की अच्छा नहीं होता, दूसरी जगह फिर फोड़ा होता है तो मूल में जाने की, आवश्यकता है कि कहीं खून की खराबी तो नहीं है । अगर खून की खराबी है तो खून कैसे ठीक किया जा सकता है इसकी दवा देने की आवश्यकता है केवल मरहम पट्टी से काम निकलने वाला नहीं । वैसे ही जो अलग-अलग घटनायें दिखाई देती हैं, उस सबके पीछे कोई सूत्र है यह देखने की आवश्यकता है । वरना हम एक-एक घटना का विरोध करते रहेंगे, इसका कोई अन्त नहीं होगा ।

दो परिस्थितियां

जब हम ऐसा देखते हैं तो दिखेगा कि दो परिस्थितियों के संयोग के कारण आज की आर्थिक दुरावस्था निर्माण हुई है । यह दो परिस्थितियाँ क्या हैं ? एक बाह्य परिस्थिति है, एक अन्तर्गत परिस्थिति है ।

साम्राज्यवादी देशों के मंसूबे

बाह्य परिस्थिति क्या है ? १९४७ में हमें स्वातंत्र्य मिला किन्तु

केवल अकेले हिंदुस्तान को ही स्वातंत्र्य मिला ऐसी बात नहीं। दूसरे महा-युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के दबाव के कारण उस समय के सफेद साम्राज्यवादी देशों को बाध्य होकर अपने-अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देनी पड़ी, इस कारण कई देशों को दूसरे महायुद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई है लेकिन यह जो सारे सफेद साम्राज्यवादी देश थे, उनका अपने-अपने देश का आर्थिक ढाँचा स्वावलम्बी नहीं था। वे देश बहुत समृद्ध हैं ऐसा किसी का ख्याल ही है वास्तव में उनकी समृद्धि का आधार उपनिवेशों का शोषण था। जैसे हिंदुस्थान से सस्ता कच्चा माल इंग्लैंड ले जाना, वहाँ पक्का माल निर्माण कर हिंदुस्थान में निर्मित माल ज्यादा रेट में बेचना। हिंदुस्थान उनकी कालोनी होने के कारण रेडी मार्केट के रूप में उनके लिए उपलब्ध था। जैसा इंग्लैंड हमारा शोषण करता था वैसे ही सफेद साम्राज्यवादी देश अपने कालोनियों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। अब परिस्थिति के दबाव के कारण स्वतन्त्रता तो देनी पड़ी लेकिन उनका आर्थिक ढाँचा तो पराव-लम्बी था। अब अगर यह आर्थिक शोषण अन्य देशों का बन्द हो जाता है तो उनका आर्थिक ढाँचा टूट जायगा ऐसी परिस्थिति है, इसके कारण वे इस फिक्र में हैं कि किस तरह से आज की स्थिति में भी अपना आर्थिक साम्राज्य, इन सभी नवस्वतन्त्र, अर्धविकसित देशों में फैलाया जाये, इस चिन्ता में यह सारे देश हैं।

श्वेत राष्ट्रों द्वारा आर्थिक साम्राज्य-निर्माण के प्रयास

आज जिस तरह से दुनिया का प्रचलित नक्शा है, उसमें इत्तिफाक से, जितने विकसित पुराने साम्राज्यवादी देश हैं यह सभी उत्तर में आ गये हैं और यह जो नवस्वतन्त्र अविकसित देश हैं, वे सारे दक्षिण में आते हैं। इसके कारण आज नई परिभाषा चल पड़ी है, उत्तरी देश व दक्षिणी देश। यह सारे उत्तरी देश इस चिन्ता में हैं कि दक्षिणी देशों का आर्थिक शोषण करते हुए अपने आर्थिक साम्राज्य का गढ़ किस तरह निर्माण किया जाए। इस चक्कर में ये सारे देश हैं किन्तु रूस को जो सुविधा उपलब्ध्य है, वह सुविधा इन देशों को उपलब्ध्य नहीं है। रूस का भी आर्थिक ढाँचा व समृद्धि स्वावलम्बी नहीं है लेकिन रूस को जिनका आर्थिक शोषण करना है वे सभी

छोटे-छोटे पूर्व योरुपीय देश, पूर्व जर्मनी, बलगारिया, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि सारे रूस के बिल्कुल बगल में हैं। देश छोटे हैं अतः प्रतिकार नहीं कर सकते क्योंकि रूसी टैंक की छाया में हैं। कभी भी गड़बड़ करेंगे तो रूसी सेना खटाक से घुस सकती है इसके कारण उनकी हिम्मत नहीं हो सकती। इस तरह बगल में ही छोटे-छोटे देशों का शोषण करने की जो सुविधा रूस को है, वह इन सफेद साम्राज्यवादी देशों को नहीं है इसके कारण नवस्वतंत्र अविकसित देशों में, अपना आर्थिक साम्राज्य निर्माण करने की दृष्टि से उनको तरह-तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। इसके लिए उनको आवश्यक हो जाता है कि इन सभी देशों में ऐसी सरकारें स्थापित होनी चाहिए जो सरकारें अपनी जनता का शोषण करने की खुली छूट, अपनी जनता का हर तरह से नाजायज फायदा उठाने की खुली छूट, साम्राज्यवादी देशों को दे दें। इस तरह की जनता विरोधी सरकारें इन सब नवस्वतंत्र देशों में स्थापित कराना उनको आवश्यक है। अगर सरकारें राष्ट्रभक्त होंगी और सोचेंगी कि हम अपने देश में किसी का आर्थिक साम्राज्य नहीं आने देंगे तो उन देशों का आर्थिक ढाँचा टूट जायगा, वह गरीब हो जायेंगे ऐसी आज की हालत है। इस दृष्टि से अपने आर्थिक साम्राज्य के अड्डे, सभी नवस्वतंत्र देशों में स्थापित करने के लिए, जनता विरोधी एवं राष्ट्रीयता विरोधी सरकारें सभी नवस्वतंत्र देशों में लाने का प्रयास उन साम्राज्यवादी देशों का है, वह उनकी आवश्यकता है—यह एक बाह्य परिस्थिति है।

आज का राजनैतिक ढाँचा देश के उपयुक्त नहीं

अब अन्तर्गत परिस्थिति क्या है ? हम जानते हैं कि हमारे देश में एक राजनैतिक ढाँचा है एक संविधान है। इस संविधान के विषय में प्रारम्भ से ही कहा गया था, कि यह इस भूमि की उपज नहीं है, पश्चिम से वैसे के वैसे उठाकर यहाँ लाया गया है अतः यह इस देश के लिए उपयुक्त नहीं होगा, यह बात राष्ट्रभक्त विचारकों ने प्रारम्भ से कही थी। पूज्य महात्मा जी ने १९१५-१६ में एक छोटी-सी किताब लिखी 'हिन्द स्वराज्य' उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे देश में ब्रिटिश पार्लमिन्ट्री सिस्टिम

ठीक नहीं चलेगी और अगर हम जबरदस्ती थोप देते हैं तो उसके घोर दुष्परिणाम होंगे। लोगों की हालत कैसी होगी उनके शब्द थे "एक वेश्या के समान जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है।" ऐसी लोगों की अवस्था हो जायेगी ऐसा उन्होंने लिखा था। पिछले ४ साल का इतिहास देखें तो गाँधी जी ने कितनी दूरदर्शिता की बात कही इसका हमें अंदाजा आ सकता है। लेनिन के साथ जिन्होंने काम किया, लेकिन बाद में स्वतंत्र विचारक होने के कारण जो कम्यूनिज्म के ऊपर उठकर अपने देश का विचार करने लगे—ऐसे एम० एन० राय, ने कहा कि इस प्रकार की सिस्टिम हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं होगी। बाबू जयप्रकाश नारायण और विनोवा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ डेमोक्रेसी अच्छी हो सकती है पोलिटिकल पार्टी का सिस्टिम यहाँ ठीक नहीं चल सकेगी। योगी अरविन्द ने स्पष्ट रूप से कहा—और काफी पहले कहा कि पोलिटिकल पार्टी सिस्टिम वह हिन्दुस्थान के लिए विदेशी पद्धति है, वह यहाँ उपयुक्त नहीं हो सकती। परमपूजनीय श्री गुरुजी ने कहा कि आज की जो पद्धति है वह पद्धति उपयुक्त नहीं, इसमें परिवर्तन लाना चाहिए, फंकशनल रेपरेजेन्टेशन लाना चाहिये। ऐसे तरह-तरह के सुझाव उन्होंने दिये। यानी जो विचारक राष्ट्रभक्त हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि यह सिस्टिम हमारे देश के लिए घातक है।

कारण स्पष्ट है—आप देखिये कि यह देश कितना गरीब है। ६० प्रतिशत लोग दलित रेखा के नीचे हैं और ४२ करोड़ लोग निरक्षर हैं, १२ करोड़ लोग केवल हस्ताक्षर कर सकते हैं, वह लिखना-पढ़ना नहीं जानते। जिस देश में गरीबी व निरक्षरता इतनी भीषण हो उस देश में आज की पद्धति में, जो जल्दबाजी में सरकार बनाना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि अपने एम० पी० व एम० एल० ए० को ज्यादा संख्या में चुन कर ले आये और एम० पी० व एम०एल० ए० को जहाँ गरीबी व निरक्षरता इतनी भीषण है ज्यादा संख्या में अगर चुनकर लाना है तो आवश्यक हो जाता है कि भ्रष्टाचार लाया जाये, पैसा बहाया जाए, तभी आज की स्थिति में ज्यादा लोगों को चुनकर लाना सम्भव हो सकता है।

ध्येयवादी राजनीति के लिये धैर्य्य चाहिये

एक व्यक्ति ने राजनीति की यह परिभाषा की, उन्होंने हालांकि

मजाक में ही कहा किन्तु बात सत्य है। उन्होंने कहा कि राजनीति एक सौम्य कला है—गरीब जनता से वोट प्राप्त करने की, एलेक्शन का धन श्रीमान लोगों से लेकर दोनों को बताने की कि हम एक से दूसरे का संरक्षण करेंगे। गरीबों से वोट और अमीरों से नोट प्राप्त करना—यह सौम्य कला यानी राजनीति है। यह बात आज बिल्कुल सही है और इसके कारण यदि हमारे में से ऐसा कोई ध्येयवादी राजनीतिक दल हो, जो सोचेगा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, राष्ट्रीय चेतना का स्तर, सार्वजनिक शिक्षा का स्तर लगातार ऊँचा उठाने की कोशिश करेंगे, देश लम्बा-चौड़ा होने के कारण जनता विशाल होने के कारण सम्पूर्ण जनता में राष्ट्रीय चेतना का व शिक्षा का स्तर ऊँचा करने में, हो सकता है कि हमें २५-३० साल लगे तो भी चलेगा—किन्तु हम साधन शुचिता छोड़ने वाले नहीं—शिक्षा का स्तर ऊँचा हो जायगा, इस तरह की राष्ट्रीय चेतनायुक्त जनता हमें सत्ता में लायगी, तब तक हम निरपेक्ष बुद्धि से काम करते रहेंगे, चाहे २५ साल लगे चाहे ३० साल लगे, इस तरह का धीरज रखने वाला जो राजनैतिक दल होगा, वही केवल साधन शुचिता को कायम रख सकता है।

जिन्हें सत्ता में आने की जल्दबाजी हो गई है उनके लिए अपरिहार्य है कि उन्हें भ्रष्टाचार करना चाहिए, वोट खरीदना चाहिए और वोट खरीदने के लिए पैसा चाहिये। पैसा, पैसा वाले से ही आता है, गरीव लोगों से पैसा नहीं आता और पैसेवाला यदि पैसा देगा, वह राजा कर्ण नहीं है, शिवि नहीं, युधिष्ठिर नहीं है—हर्षवर्धन नहीं है जो कहेगा कि आओ, मेरा खजाना लूट कर ले जाओ, तो यहाँ एक-एक पैसे के पीछे शर्त होगी। पैसे वाला यदि पैसा देता है उसके पीछे शर्त है, कि मेरे निहित स्वार्थ का, संवर्धन व रक्षण होगा। आज अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वार्थ के लिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान को बेचने के लिए तैयार, ऐसे लोग पब्लिक चौराहे पर खड़े हैं जो धीरज नहीं रख सकते कुछ सालों तक जिनकी धैर्य से काम करने की इच्छा नहीं है, जो तुरन्त कुछ न कुछ तिकड़मबाजी कर सत्ता में आना चाहते हैं और इसलिए जो काला पैसा प्राप्त करना चाहते हैं वे एक तरफ चौराहे पर खड़े हैं—राह देख रहे हैं कि मैं

इतनी लम्बी देर तक यहाँ चौराहे पर खड़ा हूं मुझे खरीदने के लिए अभी तक कोई क्यों नहीं आ रहा है, इस चिन्ता में वे वहाँ पर खड़े हैं।

विदेशी षड़यंत्रों से जनता विरोधी सरकारें

जो बाह्य परिस्थिति मैंने बताई, कि हमारे देश में और अन्य नव-स्वतंत्र देशों में, अपने आर्थिक साम्राज्य के अड्डे निर्माण करने के हेतु जहाँ जनता विरोधी सरकारें जो आर्थिक शोषण अपनी जनता का करने देंगी इस तरह की जनता विरोधी सरकारें, हमारे देश में व अन्य देशों में लाने के लिए, चाहे जितना पैसा खर्च करने की जिनकी तैयारी है, ऐसे कुछ विदेशी सरमायदार और कुछ विदेशी सरकारें बाहर खड़ी हैं और इधर यह अपने को बेचने के लिए तैयार हैं, वह उधर खरीदने के लिए तैयार हैं दोनों परि-स्थितियों का संयोग होकर, आज की आर्थिक संकट परंपरा निर्माण हुई है। इस बात पर हमको गहराई से सोचना चाहिए। दुःख की बात है कि विदेशी सरमा-दार, इनका साथ देने के लिए, यह जो सत्ता के लालच में, धीरज न रखते हुए, चाहे जो शर्तें स्वीकार करते हुए सत्ता में आने की जहाँ नेताओं की तैयारी है वैसे ही अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ के लिये, राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता को गिरवी रखते हुए, विदेशी सरमायदारों का साथ देने के लिए, हमारे यहाँ के मोनोपली सरमायेदार तैयार हुए हैं—यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है।

मैं सभी सरमायदारों की बात नहीं कर रहा क्योंकि छोटे और मध्यम सरमायदारों का हिसाब ही नहीं है। जो बड़े सरमायेदार हैं—हमारे २० एकाधिकारी घर हैं, यह अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए, विदेशी सरमाय-दारों का साथ दे रहे हैं और इस तरह मोनोपली सरमायदार और भारत सरकार, चारों का मिलकर यह षड़यंत्र है। इस षड़यंत्र की शर्त यह है कि उनके निहित स्वार्थ का संवर्धन व संरक्षण होगा और यह संवर्धन व संरक्षण यदि करना है, तो हिन्दुस्तान की गरीब जनता को कुचले बगैर, हिन्दुस्थान की गरीब जनता का शोषण किये बगैर उनके निहित स्वार्थों का संरक्षण व संवर्धन नहीं हो सकता और इसलिए, उन लोगों को जो आश्वा-सन दिये हैं उन आश्वासनों की पूर्ति करने के लिए, गरीब जनता पर

हमला करने की पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है। उसी का प्रतीक परिचायक यह बात है कि हड़ताल का अधिकार छीन लेने वाला कानून सरकार ने लाया है।

मजदूर संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन

भारतीय मजदूर संघ, एक राष्ट्रभक्त संगठन है, हम यह नहीं चाहते कि उत्पादन में बाधा आये किन्तु औद्योगिक शांति, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ मजदूरों की नहीं हो सकती अपने-अपने स्वार्थ के लिए, मालिक, मैनेजमेंट सरकार, सरकार के अफसर, यह यदि गैर जिम्मेवारी का व्यवहार करते हैं, मजदूरों की न्याय्य माँगें मानने से इनकार करते हैं ? तो फिर जायज माँगें मनवाने के लिए, अन्तिम शस्त्र के रूप में, हड़ताल करने का अधिकार मजदूरों को होना ही चाहिए, यह नीति भारतीय मजदूर संघ की है। जैसे काम करने के अधिकार को, मौलिक अधिकारों की सूची में डाला जाना चाहिए वैसे ही हड़ताल करने के अधिकार को भी, मौलिक अधिकारों की सूची में डाला जाना चाहिए। यह प्रारम्भ से हम लोगों ने कहा है। हाँ राष्ट्रभक्ति के कारण हम यह चाहते हैं, कि हड़ताल का लोकतांत्रिक अधिकार, यह छीन लेने का सरकार को अधिकार नहीं लेकिन ऐसी कानूनी मशीनरी बनानी चाहिए, जिसके कारण मजदूरों में यह विश्वास निर्माण हो कि, हड़ताल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी हमारी उचित बातें इस मशीनरी के कारण पूरी हो सकती हैं। किस तरह की मशीनरी बन सकती है इसके ठोस सुझाव भारतीय मजदूर संघ ने समय-समय पर दिए हैं।

हड़ताल का अधिकार छीनना लोकतंत्र विरोधी

हड़ताल का लोकतांत्रिक अधिकार मजदूरों का छीन लेना यह मजदूर विरोधी व लोकतंत्र विरोधी बात है। इस बात को भारतीय मजदूर संघ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह जो हमला हुआ हैं इसका प्रमुख कारण, विदेशी सरमायदार, कुछ विदेशी सरकारें, हमारे मोनोपली सरमायदार, भारत सरकार व इनका गरीब विरोधी और जनतंत्रीय विरोधी साझा मोर्चा बनना है। यह संयुक्त मोर्चा बना है उसके कारण यह हमला हो रहा है।

क्योंकि वे जानते हैं कि जब गरीबों का शोषण शुरू होगा, देश के चारों ओर फैला हुआ गाँवों का कारीगर असंगठित है, क्या खेतिहर मजदूर, क्या गाँव में फैले हुए बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार बेचारे असंगठित हैं, प्रतिकार नहीं कर सकते, प्रतिकार तो यह शहर का औद्योगिक मजदूर करेगा, इसकी कमर यदि तोड़ दी जाती है, तो बाकी लोगों का शोषण हम आराम से कर सकते हैं, कोई आवाज नहीं उठायेगा यह समझ कर संगठित मजदूरों पर यह हमला हुआ है।

तानाशाही कायम करने की नई रणनीति

यह हमला, सिर्फ संगठित मजदूरों पर है ऐसा अगर किसी का ख्याल होगा तो वह गलत बात है। यह जो संयुक्त मोर्चा है; सरमायदारों व सरकार का, इसका आगे चलकर क्या मतलब होता है यह भी देखना चाहिए। जून १९७५ में तानाशाही लाने का प्रयास हुआ, क्यों हुआ ? कारण स्पष्ट है। गरीब विरोधी नीतियों को लेकर यदि सरकार चलती है, सरकार के पास प्रोपेगण्डा मशीनरी अच्छी होगी, लेकिन ज्यादा देर तक जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। गरीब लोग नेताओं का सच्चा स्वरूप समझ जायेंगे और यदि उस अवस्था में लोकतंत्र कायम रहता है और चुनाव होते हैं, तो आज के सरकारी दल को फिर से चुनकर लाना, असंभव हो जायगा। और इस दृष्टि से यह सोचा गया कि लोकतंत्र को समाप्त करते हुए तानाशाही लानी चाहिए। ताकि अपने व्यक्तिगत पारिवारिक स्वार्थ सिद्ध होते रह सकें, चुनाव का झंझट नहीं, तानाशाही कायम हो जायगी। विदेशी व देशी सरमायदारों का लाभ बनता रहेगा और भारत सरकार की अपनी कुर्सी बनी रहेगी। ७५ में यह विचार था और आज भी यह विचार है। लेकिन जून १९७५ में, जो गलतियाँ की थीं, उनको न दोहराने का विचार सरकार ने किया है। उस समय की सबसे बड़ी गलती यह थी कि एकदम आपातकाल लाया गया इसके कारण एकट्ठे एक ही समय सबको दुश्मन बनाया गया और इसके दुष्परिणाम १९ महीने के बाद उनको भुगतने पड़े। इस गलती को दोबारा न दुहराने का विचार सरकार ने किया है। यह नई रणनीति सरकार ने ली है।

यह रणनीति है, एक-एक को पकड़ कर उसकी पिटाई करना और तब तक बाकी जनता को समझाना कि यह बदमाश थे, गड़बड़ कर रहे थे इसलिए इनकी पिटाई हो रही है आप से हमारी दोस्ती है, आपके खिलाफ कुछ नहीं है। ऐसा बाकी लोगों को शांत रखना। एक की पिटाई हो जाएगी, फिर दूसरे को पिटाई के लिए पकड़ना—इस तरह एक-एक को पकड़ के पिटाई करना यह नई रणनीति सरकार ने अपनाई है और इसमें पहला नम्बर संगठित मजदूरों का आया हुआ है।

दूसरी बारी प्रेस की

यह आखिरी नम्बर नहीं है, मजदर यदि इस लड़ाई में हार जाते हैं। मजदूर-आंदोलन की कमर अगर टूट जाती है तो दूसरा नम्बर प्रेस का आने वाला है, यह बात मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं। आगे नम्बर आने वाला है इतनी ही बात नहीं, आज समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होता, किन्तु मैं जानता हूं कि जो बड़े राष्ट्रीय वृत्त पत्र हैं, जिनका सरकुलेशन बहुत बड़ा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसके कारण सरकार के खिलाफ टीका-टिप्पणी करने का साहस जो रख सकते हैं ऐसे बड़े राष्ट्रीय वृत्त पत्रों के अन्तर्गत कारोबार में हस्तक्षेप करते हुए गड़बड़ निर्माण करने का प्रयास आज भी अप्रत्यक्ष अपने एजेण्टों के द्वारा सरकार ने किया हुआ है। और मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जब मजदूर आंदोलन की कमर टूट जायगी, दूसरा नम्बर वृत्त पत्रों का आयगा और वह खतम हो जायगा।

तीसरा प्रहार अन्य लोकतांत्रिक शक्तियों पर होगा

तीसरा नम्बर सभी प्रकार की लोकतांत्रिक शक्तियों का आयगा, इस तरह एक-एक कर पकड़ कर पिटाई करना, यह नई रणनीति सरकार ने तय की है। माने इस लड़ाई में मजदूरों की पिटाई हो रही है, लोकतन्त्र की समर्थक शक्तियाँ यदि जागरुक न रहीं इस लड़ाई का सच्चा स्वरूप उन्होंने नहीं समझ लिया और मजदूरों की यदि हार हो जाती है तो लोकतान्त्रिक शक्तियों को बहुत बड़ी चोट पहुंचने वाली है किन्तु यदि इस लड़ाई में मज-दूरों की विजय होती है तो तानाशाही लाने वाली शक्तियों को बड़ी चोट

पहुंचने वाली है। माने यह लड़ाई यद्यपि बाहर से दीखने के लिए केवल मजदूरों की अपने अधिकारों की लड़ाई होगी वास्तव में यह एक शृंखला की कड़ी है।

सरकार द्वारा मजदूरों पर आक्रमण तानाशाही-शृंखला की एक कड़ी

सरकार का यह आक्रमण, यह अकेली घटना नहीं—एक शृंखला की पहली कड़ी है और इसमें यदि मजदूर हार जाता है, तो स्वतंत्रता को धक्का लगेगा। यह मजदूर की लड़ाई केवल मजदूर के हड़ताल के अधिकार की लड़ाई नहीं तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है यह बात सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को समझना चाहिए। हमारे इधर एक कहावत है कि महिलायें सुबह के समय जब अनाज के दाने पीसने के लिए बैठती हैं तो कुछ अनाज के दाने चक्की में चले जाते हैं और कुछ अनाज के दाने बाहर किसी महिला के हाथ सूप में आनन्द से नाचते रहते हैं। यह जो सूप में आनन्द से नाचने वाले अनाज के दाने हैं यह चक्की में जो दाने गये हैं उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, इनकी अच्छी पिसाई हो रही है होने दो, लेकिन वे नहीं जानते कि दस मिनट बाद उनका भी नम्बर आने वाला है, उनको भी चक्की में डाला जायगा उनकी वैसे ही पिसाई होगी जसी आज इनकी हो रही है।

केवल श्रमिकों की नहीं तो यह 'लोकतन्त्र बचाओ' की लड़ाई है

सरकार के प्रोपेगेंडा के कारण लोकतंत्र के समर्थक लोग भी ऐसा मान रहे हैं कि यह तो मजदूरों की लड़ाई है हमें इसमें लेना-देना क्या है? किंतु वे नहीं जानते कि यदि इसमें मजदूरों की पिसाई पूरी तरह से हो गई, तो अगला नम्बर तुम्हारा भी आने वाला है—लोकतंत्र के समर्थक लोग इस बात को अभी जानते नहीं हैं। यदि उन्होंने यह जागरुकता नहीं रखी और इस लड़ाई में मजदूर आंदोलन का पूरा समर्थन नहीं किया, मजदूर हार जायगा इतनी ही बात नहीं तो लोकतंत्र को समाप्त करने के प्रयास में, तानाशाही लाने के प्रयास में भारत सरकार को बहुत बड़ा समर्थन व शक्ति प्राप्त होगी। वह बात सोच समझकर सभी लोकतंत्र के समर्थकों को ध्यान

में रखनी चाहिए और यह लड़ाई केवल मजदूरों के अधिकार की लड़ाई नहीं, यह लोकतंत्र के बचाओ की लड़ाई है, यह समझकर इस लड़ाई में मजदूरों का पूरी ताकत से समर्थन करना चाहिए।

संकट परम्परा का मूल कारण—स्वाभिमान शून्यता

वैसे ही इस संकट परम्परा का मूल कारण क्या है इसका विचार सभी राष्ट्र भक्त लोगों को करने की आवश्यकता है। मैं केवल मजदूर क्षेत्र तक सीमित बात नहीं कर रहा। आज चारों ओर एक निराशा का वायु-मण्डल है। सभी देशभक्त सोच रहे हैं कि क्या होगा ? ३४ साल तक हम कुछ बना नहीं पाए, हमारी तो एक के बाद एक अधोगति होती जा रही है, मालूम होता है कि हमारे अन्दर वह क्षमतायें नहीं हैं जिनके आधार पर देश को ऊपर लाया जा सकता है। इस तरह का आत्मग्लानि का विचार देशभक्त लोगों के मन में निर्माण हो रहा है। हम देखते हैं कि दूसरा महा-युद्ध, जर्मनी व जापान की भूमि पर लड़ा गया था, इसके कारण वे देश उद्ध्वस्त हो गए थे, लेकिन इतने थोड़े समय में दोनों ने अपने राष्ट्र का इतना निर्माण किया कि आज जर्मनी की दहशत सारे योरुप पर है और आर्थिक दृष्टि से जापान का एन अमेरिका के डालर को धक्का दे रहा है— इतनी प्रगति दोनों देशों ने की। हमारे देश में तो महायुद्ध लड़ा नहीं गया था, तो भी हम नीचे जा रहे हैं। लोगों के मन में यह भ्रम है, कि हम नीचे जा रहे हैं इसका कारण, ऊपर उठने की हमारी क्षमता नहीं और इसलिए अब आशा के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इस प्रकार का विचार सर्वसाधारण नागरिक के मन में आ रहा है। बात बिल्कुल गलत है। हमारे देश में वह सारी क्षमतायें हैं जिसके आधार पर किसी भी राष्ट्र को दुनिया का एक महान राष्ट्र बनाया जा सकता है। हमारे पास साधनों की शक्ति है, हमारे पास मनुष्य बल है, हमारे पास, वह गुणवत्ता है जिसके कारण आज पश्चिमी देश प्रगति कर रहे हैं। अमेरिका का 'नासा' जहाँ आकाशीय विज्ञान की प्रयोगशाला है वहाँ अगर आप जायेंगे तो अमेरिकन व जर्मन वैज्ञानिक व टेकनालाजिस्ट के कंधे से कंधा लगाकर हमारे भारतीय वैज्ञानिक और टेक-नालाजिस्ट काम कर रहे हैं और वहाँ उनको समान इज्जत दी जाती है यह

आपको दिखाई देगा। हम विज्ञान में, टेकनालाजी में, गुणवत्ता में कम नहीं। ऊपर आने के लिए वह सारा मसाला हमारे पास तैयार है। फिर हम नीचे क्यों जा रहे हैं ? इसका एक ही कारण है कि शासन चलाने वाले नेताओं में राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं।

अपने पैरों पर खड़े होनें की आवश्यकता

हम अपने राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, यहआकांक्षा नहीं, केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ के लिए सत्ता का उपयोग करने की सीमित इच्छा हैं, राष्ट्र को बड़ा बनाने की इच्छा नहीं है। इसके कारण आप जानते हैं हमारे देश में जो योजनायें चल रही हैं वह भारतीयों द्वारा चलाई हुई योजनायें नहीं हैं। ऐसा दीखता होगा कि प्लानिंग कमीशन के सभी सदस्य भारतीय हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन व निर्देशन सारा विदेशी विशेषज्ञ कर रहे हैं और विदेशी विशेषज्ञ अपने-अपने देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमारे देश की योजनायें बना रहे हैं। माने हिन्दुस्थान का प्लानिंग विदेशों की सुविधा को ध्यान में रखकर हो रहा है, यह बात चारों ओर दिखाई दे रही है, हम अपने बल पर खड़े हो जायें, वैसी आज की स्थिति नहीं है।

चीन स्वावलम्बी कैसे बना ?

हमारे नजदीक चीन है उसका उदाहरण हम लेंगे। चीन के माओ, जितने कम्यूनिस्ट थे उतने अधिक राष्ट्र भक्त भी थे। उन्होंने किस तरह व्यवहार किया, हमारे नेता किस तरह व्यवहार करते हैं, एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि १९४८ में चीन में राज्य क्रांति हुई कम्यूनिस्टों के हाथ में चीन की बागडोर आई। उस समय चीन अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का वायुमण्डल था, सारे दुनिया के कम्यूनिस्ट देश एक हैं, यह स्वप्न रंजन चल रहा था। रूसी चीनी भाई-भाई के नारे चल रहे थे और इस कारण जो चीन की प्रथम पंचवार्षिक योजना थी वह पूरी तरह से रूस ने तैयार की हुई थी। योजना बनाने वाले रूसी, योजना के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञ सारे रूसी थे। प्लान व प्रोजक्ट

की सारी मशीनरी भी रूसी थी। उनको लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद है, वह आए क्या हम रहे क्या—एक ही बात है, ऐसा स्वप्न रंजन चल रहा था। लेकिन धीरे-धीरे माओ के यह ख्याल में आया कि यह अन्तर्राष्ट्रीयता का नारा धोखा है। रूस अपना आर्थिक साम्राज्य यहाँ फैलाना चाहता है, आर्थिक शोषण करना चाहता है। यह दादागीरी हम नहीं चलने देंगे। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, माओ और उनके साथियों में जाग्रत हुई और उन्होंने निश्चय किया कि रूस को यहाँ से हटाना है। कोल्ड वार शुरू हुई और १९६० में रूस व चीन का सम्बन्ध विच्छेद हो गया। जिस समय सम्बन्ध विच्छेद हुआ उस समय, रूस ने सोचा चीन नया राष्ट्र है इस पर दबाव लाया जा सकता है, दबाव की नीति लाई जा सकती है और इस दृष्टि से जैसे ही सम्बन्ध विच्छेद हुआ वैसे ही उन्होंने तुरन्त दबाव लाने के लिए अपनी सारी पूँजी वापस ले गए अपने सारे विशेषज्ञों को वापस बुला लिया और अपनी सारी मशीनरी वापस ले गए, क्योंकि सारे प्लान व प्रोजेक्ट रूसी मशीनरी के सहारे चल रहे थे अतः वे सोच रहे थे कि इसके कारण माओ दब जायगा झुक जायगा और हमारी शरण में आ जायगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ वे धीरज के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ खड़े हुए। चीन की जो परम्परागत पद्धतियां व योजनायें थीं उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, लोग समझ सकें इतना तकनीकी जानकारी देते हुए उन परंपरागत स्कीमों को बढ़ावा दिया। रशियन विशेषज्ञों ने कुछ सिखाया नहीं था तो भी देख-देखकर उनके नीचे काम करने वाले चीनी लोगों को सीखना चाहिए उस प्रक्रिया में से अपने विशेषज्ञों को ट्रायल एण्ड एरर पद्धति से अपने प्रोजेक्टस को चलाने की इजाजत दी। अपने वैज्ञानिकों और अपने तकनीकियों के भरोसे देश को निर्माण करने का प्रयास किया।

एक उदाहरण

आज हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान-शून्य सरकारी नौकर किस तरह काम कर रहे—एक छोटा उदाहरण तुलनात्मक विवेचन के लिए आपके ख्याल में आ जाये इसलिए मैं देना चाहता हूं। अभी कलकत्ता के पास हुगली नदी पर दूसरा पुल बनाने का कार्य चल रहा है। वास्तव में यह पुल

बनाने के लिए जिस-जिस कौशल्य की आवश्यकता है वह सारा कौशल्य हमारे देश में है। जो योजना कर सकते, बिल्यूप्रिंट बना सकते ऐसे इंजीनियर व तकनीकी हैं—सभी भारतीय हमारे पास हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से लेकर अब तक हमारे किसी इंजीनियर को उसमें नहीं लिया गया न हमारे विशेषज्ञ की सहायता ली गई। विदेशी विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीकी आये और उनके नीचे काम करने का कार्य भारतीयों को बताया जा रहा है। इसके तुलना में दूसरा उदाहरण देखिये। १९६० में जब यह दिखाई देने लगा कि अब रूस से सम्बन्ध विच्छेद होगा, उसके १-१॥ साल पहले वहाँ की एक बड़ी नदी, यांगसी, पर पुल बनाने का कार्य चल रहा था। रूसी मशीनरी थी रूसी विशेषज्ञ थे। थोड़े दिन की बातचीत के बाद सरकार ने उनको बताया कि महाराज आप सब लोगों को हम दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, वहाँ बड़ा जरूरी काम है आपके बिना हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हम जायेंगे तो इस पुल का काम अधूरा रहेगा, सरकार ने कहा कि इसे अधूरा रहने दीजिए वहाँ ज्यादा जरूरी काम है। सारी फौज रूसी विशेषज्ञों की वहाँ भेजी गई। कुछ महीनों के बाद उनको दोबारा यहाँ लाया गया उनको आश्चर्य हुआ कि पुल का कार्य पूरा हो गया है। सरकार ने पूछा कि आपके जो स्पेसीफिकेशंस थे, उसमें और जो पुल तैयार हुआ है उसमें कितना अन्तर है। उन्होंने खोज कर निकाला केवल १.५ सेंटीमीटर का अन्तर था। रूसी विशेषज्ञों ने चीनी विशेषज्ञों को कुछ सिखाया नहीं था, वे केवल अनुभव के आधार पर सीखे, केवल १.५ सेंटीमीटर का अंतर था। उसके बाद उनको आश्चर्य का धक्का देने वाली एक घटना हुई। उनको एक दूसरे स्थान पर ले गए। पुल बनाने की जो रूसी मशीनरी थी ऐसे दो सेट वहाँ रखे गए थे। उनको बताया गया कि इसमें एक सेट आपका है एक सेट हमने तैयार किया है आपका सेट कौन सा है और हमारा सेट कौन सा है यह जरा पहचान लीजिए, वह पहचान नहीं सके। जब यह सारे विशेषज्ञ दूसरी जगह गये थे—बीच की कालावधि में इस माडेल की पूरी नकल इतने अच्छे ढंग से उन्होंने की वह पहचान नहीं सके कि इसमें रूसी मशीनरी कौन सी है और चीनी मशीनरी कौन सी है।

यह महान प्रयास इस तरह का जगह-जगह जो किया इसके कारण उन्होंने अपने राष्ट्र के सामने राष्ट्रीय स्वाभिमान की घोषणा रखी। केवल भाषण में घोषणा नहीं की क्या राष्ट्रीय स्वावलम्बन का कुछ भी मतलब हो सकता है अगर विदेशों से गेहूं लाकर यहाँ खाया जाए। उन्होंने यह एक लक्ष्य रखा, कि हमारा राष्ट्रीय पुन: उत्थान हमारे ही प्रयासों के आधार पर होगा यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की घोषणा उन्होंने की। एक महान प्रयास करते हुए हम देखते हैं कि चीन में उनका राज्य हमारे बाद आया, जैसे मैंने कहा कि माओ जितना कम्यूनिस्ट था उससे अधिक कट्टर राष्ट्र भक्त था, राष्ट्रभक्ति के आधार पर महान प्रयास करते हुए आज चीन हमसे आगे निकल गया, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है।

राष्ट्रीय स्वावलम्बन का निश्चय करें

यदि हमने प्रयास किया होता, उसमें हम असफल होते तब तो निराशा की बात थी। इस दिशा में हमने प्रयास ही नहीं किया। हम तो दुनिया को शांति देने के लिए निकले और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ के लिए हिंदुस्थान की आर्थिक स्वतंत्रता, हिंदुस्थान का सार्वभौमत्व, विदेशियों को बेचने में कोई शरम नहीं लगी। ऐसी हमारे यहाँ के नेताओं की आज अवस्था है। माने आज यदि हमारी गिरावट है, वह इसके कारण नहीं कि ऊपर उठने की हमारी क्षमता नहीं तो हर तरह की क्षमतायें हमारे देश के अन्दर हैं। हम यदि राष्ट्रीय स्वाभिमान से युक्त होकर, यह निश्चय करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पुन: उत्थान हमारे ही प्रयासों के आधार के ऊपर करेंगे तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस शताब्दि के अन्त तक हमारा देश दुनिया के प्रथम श्रेणी के देश में जाकर बैठ सकता है। इतनी क्षमता हमारे देश के अन्दर है। क्षमताओं का अभाव नहीं तो इच्छाशक्ति का अभाव है। और इस इच्छाशक्ति के अभाव के कारण राष्ट्रीय स्वाभिमान को भूलकर जहाँ १९४७ में बड़ी कुर्बानी के बाद हमने राजनैतिक स्वातंत्र्य प्राप्त किया, आज फिर से हमारी स्वतंत्रता व सार्वभौमत्व बेचने के लिए नेता लोग तैयार हो गये हैं। इसी में से आर्थिक संकट परम्परा निर्माण हुई है यह कार्य–कारणभाव ख्याल में रखना चाहिए। विदेशियों की

स्निधा के लिए, हमारी गरीब जनता पर और मजदूरों पर कुठाराघात हो रहा यह कार्य-कारणभाव ध्यान में रखना चाहिए।

लोकतन्त्र की लड़ाई

यह यदि हम ध्यान में रखते हैं तो यह लड़ाई सरकार-विरोधी मजदूरों की लड़ाई है, यह सिर्फ मजदूरों की लड़ाई है ऐसा समझना गलत होगा। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है और इस दृष्टि से सभी राष्ट्र भक्त लोगों ने इस लड़ाई में मजदूरों का समर्थन करना चाहिए। याने यह लड़ाई केवल संगठित मजदूरोंकी नहीं तो सम्पूर्ण गरीब जनता की है। केवल गरीब जनता की नहीं, आम जनता की है। लोकतंत्र के समर्थकों की यह लड़ाई है। राष्ट्रभक्त शक्तियों की यह लड़ाई है। इस लड़ाई का सच्चा स्वरूप समझते हुए लोकतंत्र के सभी समर्थक राष्ट्रीय स्वाभिमान की चिन्ता करने वाले राष्ट्रभक्त—सभी लोगों ने इस संघर्ष में मजदूरों का साथ देना चाहिए। यह बात आज जनता को समझाने की आवश्यकता है।

आज के इस अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बोलना उचित भी नहीं होगा, आवश्यक भी नहीं होगा किन्तु मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्र के आर्थिक स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व के लिए जो बड़ा खतरा सामने दिखाई पड़ रहा है इसके कारण स्वाभाविक रूप से मन में आने वाली कुछ बातें आपके सामने रखी हैं।